भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. : 2619

उत्तर देने की तारीख : 05.08.2025

पीएम-अजय का कार्यान्वयन

2619. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में, विशेषकर अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों में अवसंरचना के विकास, आजीविका सृजन और शैक्षिक सहायता के संदर्भ में प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय) के कार्यान्वयन का मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हाँ, तो पीएम-अजय के अंतर्गत मॉडल गांवों के रूप में चयनित और विकसित किए गए गांवों की ओडिशा सहित कुल संख्या कितनी है;

(ग) 2023 में योजना के शुभारंभ के बाद से आवंटित और उपयोग की गई निधि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पीएम-अजय या इसके पूर्ववर्ती घटकों के अंतर्गत, विशेषकर बलांगिर जिले में, अनुसूचित जाति बहुल गांवों को कवर किया गया है; और

(ङ) यदि हाँ, तो आजीविका सहायता, कौशल प्रशिक्षण और मूलभूत सुविधाओं तक पहुँच के संदर्भ में क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री रामदास आठवले)

(क): प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय) एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो वर्ष 2021-22 से क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना के तीन संघटक हैं, नामतः (i) 'आदर्श ग्राम', (ii) 'अनुसूचित जाति (एससी) समुदायों की सामाजिक-आर्थिक बेहतरी के लिए जिला/राज्य स्तरीय परियोजनाओं के लिए अनुदान सहायता' और (iii) 'छात्रावास'। प्रभावी कार्यान्वयन और अनुवीक्षण के लिए, योजना के प्रत्येक संघटक के लिए वास्तविक काल डेटा प्राप्त करने हेतु एक केंद्रीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) पोर्टल तैयार किया गया है। नियमित समीक्षाओं, राज्यवार प्रदर्शन ट्रैकिंग और केंद्र, राज्य एवं

ग्रामस्तरीय समितियों के निरीक्षण के माध्यम से योजना के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण किया जाता है। साथ ही, नीति आयोग द्वारा प्रभाव मूल्यांकन का कार्य भी किया गया है।

(ख): पीएम-अजय योजना के आदर्श ग्राम संघटक के अंतर्गत 29,907 गांवों का चयन किया गया है, जिनमें से 12,175 गांवों को आदर्श ग्राम घोषित किया गया है। ओडिशा में 1,456 गांवों का चयन किया गया है, जिनमें से 978 गांवों को आदर्श ग्राम घोषित किया गया है।

(ग): वर्ष 2021-22 से पीएम-अजय योजना के अंतर्गत जारी केंद्रीय सहायता का राज्यवार विवरण **संलग्नक** में दिया गया है।

(घ) और (ङ): बलांगीर जिले में, पीएम-अजय के आदर्श ग्राम संघटक के तहत, 30 गांवों की पहचान की गई है, इनमें से 23 गांवों में सीसी रोड, आंगनवाड़ी, शौचालय, नालियों, स्ट्रीट लाइट, सोख्ता गड्ढे, सौर लाइट, हैंडपंप आदि के निर्माण जैसे कार्यों की शुरुआत करके इन्हें आदर्श ग्राम घोषित किया गया है। पीएम-अजय योजना के अनुदान घटक के अंतर्गत, कौशल प्रशिक्षण पहल के अंतर्गत 121 लाभार्थियों को लाभ मिला है और आजीविका सहायता पहल के अंतर्गत 99 लाभार्थियों को लाभ मिला है तथा बुनियादी ढांचा विकास पहल के अंतर्गत 20 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

संलग्नक

पीएम-अजय का कार्यान्वयन पर लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं. 2619 के संबंध में संलग्नक

वर्ष 2021-22 से पीएम-अजय योजना के तहत जारी केंद्रीय सहायता का विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	जारी की गई धनराशि (रु. करोड़ में)
1	आंध्र प्रदेश	123.8
2	असम	41.26
3	बिहार	65.25
4	चंडीगढ़	0.46
5	छतीसगढ़	39.87
6	दिल्ली	0
7	गोवा	0
8	गुजरात	3.19
9	हरियाणा	8.09
10	हिमाचल प्रदेश	32.77
11	जम्मू एवं कश्मीर	19.87
12	झारखंड	68.8
13	कर्नाटक	246.56
14	केरल	8.84
15	मध्य प्रदेश	73.52
16	महाराष्ट्र	82.35
17	मणिपुर	12.36
18	मेघालय	0
19	मिजोरम	3.93
20	नागालैंड	44.62
21	ओडिशा	208.06
22	पुदुचेरी	0.03
23	पंजाब	87.13
24	राजस्थान	87.87
25	सिक्किम	11.08
26	तमिलनाडु	919.04
27	तेलंगाना	47.91
28	त्रिपुरा	65.31
29	उत्तर प्रदेश	622.34
30	उत्तराखंड	23.61
31	पश्चिम बंगाल	307.62
कुल		**3255.54**

*****